>

Title: Need to resume the construction of Pala Maneri and Vishnugad Pipalkoti hydro-electric projects and to continue the construction of Lohari Nagpala power project in Uttarakhand.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार ने एक दशक से बंद पड़ी मनेरीभाली द्वितीय जल विद्युत परियोजना शुरू की जो अब 304 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को दे रही है। तत्पश्चात 480 मेगावाट की पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना भी शुरू की गई, जिसे अब वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा बंद करवा दिया गया है।

अब राज्य की सरकार ने एन.टी.पी.सी. द्वारा बनाई जा रही 600 मेगावाट की लोहारी नागपाला परियोजना को भी बंद कराने की सिफारिश प्रधानमंत्री से की है। जबकि स्थिति यह है कि इस परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं तथा इस परियोजना को बंद करने पर हजारों करोड़ रूपए और खर्च होंगे। इसी प्रकार 444 मेगावाट की विष्णुगाद पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना भी अटकी पड़ी है। इस परियोजना पर भी अब तक 100 करोड़ खर्च हो चुके हैं। उत्तराखंड को देश के पॉवर हाउस के रूप में प्रचारित किया गया तो वहां उद्योगों का तांता लग गया। लेकिन अब, जब नई परियोजनाएं बंद होने लगी हैं तो ऊर्जा राज्य बिजली संकट में फंसने लगा है और उद्योगों का पलायन होने लगा है। अगर इसी तरह परियोजनाएं बंद होती रहीं तो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सारे देश में कहीं भी नयी परियोजना बनाना असंभव हो जायेगा और सन् 2012 तक सरकार का हर घर को बिजली देने का सपना अधूरा ही रह जायेगा।

सरकार इन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के विस्थापन, पुनर्वास एवं मूलभूत समस्याओं पर पुनर्विचार कर सकती है परन्तु हमें अपनी नैसर्गिक ऊर्जा पैदा करने की क्षमता खोनी नहीं चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि पर्यावरण पर अवश्य नजर रखे लेकिन यह अनावश्यक रूप से उत्तराखंड जैसे पिछड़े राज्य के विकास में बाधक नहीं बननी चाहिए।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए तथा देश के विकास के लिए गंगा से ऊर्जा (बिजली) पैदा करने के लिए तत्काल पाला मनेरी और विष्णुगाद पीपलकोटि परियोजनाओं को शुरू किया जाये और लोहारी नागपाला परियोजना को बंद करने की सिफारिश को न माने। मेरी मांग है कि राष्ट्रहित में इन परियोजनाओं का निर्माण तत्काल पूरा किया जाये।